FINACIAL EXPRESS 11/09/2018

ire solar panels — d for a year, ending 19, and the tax was o 20% for the six January 29, 2020, or the subsequent .

is seen to increase s by 50 paise per r CARE Ratings, discouraging elec-

zones (SEZs), which currently accommodate 40% of 10 giga-watt (GW) of solar module manufacturing units and 60% of 3 GW of cells production base.

However, domestic manufacturers believe that this step would salvage the industry, currently stressed with facing uneven competition from

Sunil Rathi, director, Waaree Energies.

Imported solar modules are 8-10% cheaper than those made in India, making them vital for cheap renewable power — solar modules comprise about 60% of total project costs. About 88% of module requirements are met through imports.

l suggests creation of stressed asset to deal with stuck housing projects

IR
tember 10

IC APPROACH is olve the problem of affected homebuy- g because of stalled here the builders are navigate forward straints, housing affairs minister ngh Puri has said. d that a high-pow- ittee, set up at the the Uttar Pradesh nt, has suggested n of a stressed asset al with incomplete here builders don't esources to finish s.

as speaking at the nal workshop on n Pune.

g at the event, the urther said partial an be provided for cts so they can ed. This would pro- relief to the hassled rs who are dealing in blow of having and also have their ck as they are pay- e added. Stressed are a way to bridge he interim to navi- h the current mess ld set a template,

ister further said many who are still eep things outside

MoS for housing and urban affairs Hardeep Singh Puri

Stressed asset fund is a way to bridge the gap in the interim to navigate through the current mess and it could set a template, Union minister HS Puri said

vetting. Puri added that the government will not allow any dilution or tweaking of the Rera Act.

SHIVALIK AGRO POLY PRODUCTS LTD.

Regd. Office: Plot No. 1, Sector 3, Industrial Area, Parwanoo (H.P.)
Phone Nos- 0172-2227087-88, Fax: 0172-2270349. Email:bljain@sappl.co.in
Website: www.shivalikagropoly.com CIN: U15131HP1976PLC003703

COMPANY NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and other applicable provisions that Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 20th September, 2018 to 25th September, 2018 (both days inclusive) for the purposes of Annual General Meeting to be held on Friday, 28th September, 2018 at 12.30 Noon at the Registered Office of the Company. Further, the record date has been fixed for 25th September, 2018 for the purposes of dividend @ 25% i.e. Rs. 2.50 per equity share to the members, as recommended by the board.

For SHIVALIK AGRO POLY PRODUCTS LTD.
Place: Mohali
Dated: 10th September, 2018
B.L. Jain
Company Secretary

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

E-TENDER PRESS NOTICE NO. 41/FO [Hort.] N/W/2018 19 Pt-I (B)

On line Item Rate Tenders are invited/Re-invited through e-tendering mode for the following works by the Dy. Director (Hort.)-III, B2B, Janakpuri, New Delhi-110058 & Dy. Director (Hort.)-VIII, B2B, Janakpuri, New Deli-110058. On behalf of Delhi Development Authority from the approved and eligible contractors registered under Horticulture Category only of DDA & CPWD and those of appropriate list of MES, BSNL and Railway. The last date and time of submission of tender is

Branch Name	Name of t Borrower and Guaran
Corporation Bank Harthala Branch Kanth Road Harthala Moradabad-244001 (U.P.)	M/s Vishal Dairy Prop. Mrs. Laxmi Da Laxmi W/o Shri Ra Himgiri Tiraha, Near Godam, Sonakpur Moradabad (U.P.) Guarantor : Mr. Sa Vishnoi S/o Shri Anil K Road, Harthala, Near Chowki, Moradabad (U

Date - 10.09.2018

BRANCH: JALANDHA

LAST DATE

LAST DATE & TIME O

Whereas under section 13(2) of the 'Secu the recovery of sum as mentioned against Assets and Enforcement of Security Inter Borrowers. Whereas sale of the secured as The General Public is invited to bid either p

Name of Branch & Account/ Borrower	Desc along w (Ow
JALANDHAR ROAD KAPURTHALA M/s SARV HITKARI EDUCATIONAL SOCIETY, New Delhi (Regd)	1. Property Bhawanipur constructed (A) Equitab with area of

khasra no 100/153 to 155 khasra 0,9/8-0,10/8-0,14/3/3-0,22//14 /2/0- 182/281 khasra no 11//21/1/2-2,1 which ¼ share comes to 6-1 vide S Kapurthala as per Jamabandi for the (B) Equitable Mortgage of Land & 2,14//1/8-0,10/8-0,11/2/2-0,15//6/1 12,6/2/6-7,7/1/1-12,15//24/2/2/1-3,2 khata no-101/156 to 160 khas 0,14//19/2/0-1,24/2/5-15 total 65-0 in 16K 0M situated at village Bhawanip Society New Delhi (C) Equitable Mortgage of Land & no 14//12/1/2/0-6,15//24/2/0-14,16/2 4325 dated 15.03.2000. So the Lan Educational Society New Delhi (D) Equitable Mortgage of Land & 0,19//25/34/0-2 total 24K-4M in whi 0,14/3/3-0 total 45-0 in which 170/900 0,2/8-0,14//19/2/0-1,24/2/5-15 total Bhawanipur Distt. Kapurthala as per (E) Equitable Mortgage of Land & B 0,19//25/34/0-2 total 24K-4M in which no. khasra 11//22/2/0-8,14//2/1/2-8,9 3,22//14/2/0-12,23//7/6-14,8/8-0, 9/8- 0,22//5/8-0,23//3/8-0,23//1/8-0,2/8-0, 10M Total land 41K-8M vide Sale de 2012-13 in the name of/ownership Sa (F) Equitable Mortgage of Land & Buil share comes to 3K-2½ M and khata comes to 5K-10M and khata 121/18 sharecomes to 8½ M and khata no 31 to 3K-15M and khata 210/306 khsara

DANIK JAGRAN 11/09/2018

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, अयोध्या मामले में कब तक चलेगा ट्रायल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अयोध्या मामले की सुनवाई कर रहे विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि वह पहले यह बताएं कि ट्रायल कब तक पूरा कर लेंगे? उनसे सील बंद लिफाफे में जवाब मांगा गया है। विशेष जज ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर प्रोन्नति की मांग की है। जाहिर है कि उनके जवाब के बाद ही कोर्ट कोई फैसला लेगा।

तल्खी

- विशेष जज से मांगी सील बंद लिफाफे में ट्रायल की स्थिति रिपोर्ट
- सुनवाई कर रहे विशेष जज ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मांगी है प्रोन्नति

सोमवार को न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और इंदु मल्होत्रा की पीठ ने विशेष जज की ओर से पेश वकील रवि सीकरी और मयूरी रघुवंशी की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया। इससे पहले वकीलों ने गत वर्ष 19 अप्रैल के आदेश में बदलाव करने की गुहार लगाते हुए कहा कि इससे विशेष जज की प्रोन्नति रुक गई है। हाई कोर्ट ने गत एक जून को बदायूं के जिला जज के पद पर उनकी नियुक्ति और स्थानांतरण की अधिसूचना जारी की थी। लेकि[illegible] दिन एक और अधिसूचना जारी हुई, जिसमें उनकी जिला जज पद पर नियुक्ति और स्थानांतरण को अगले आदेश तक के लिए निरस्त कर दिया गया। इसके पीछे ट्रायल पूरा होने तक जज का स्थानांतरण नहीं करने के आदेश को आधार बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गत वर्ष 19 अप्रैल को आडवाणी, जोशी और उमा भारती सहित भाजपा और विहिप के 14 नेताओं के खिलाफ अयोध्या में ढांचा ढहाने की साजिश का मुकदमा चलाए जाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने नेताओं का मुकदमा रायबरेली की अदालत से अयोध्या प्रकरण की सुनवाई कर रहे लखनऊ के विशेष जज की अदालत में स्थानांतरित कर दिया था।

साथ ही रोजाना सुनवाई कर दो साल में ट्रायल पूरा करने और इस बीच जज का स्थानांतरण नहीं किए जाने का भी आदेश दिया था। अर्जी में विशेष जज ने कहा है कि वह आठ जून, 1990 को मुंसिफ मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए थे। उनका 28 साल का बेदाग करियर है। उन्होंने ईमानदारी और निष्ठा से काम किया। अब वह 59 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति के मुकाम पर पहुंचने वाले हैं।

बादल की जान बचाने वालों में कई अहम किरदार हैं, मगर सभी चकित, क्योंकि ऐसे मामलों में जिंदगी की जंग जीतना बहुत मुश्किल लगता है। अगर सर्जरी हो भी गई तो संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। अलबत्ता, उसका न केवल सफल ऑपरेशन हुआ, बल्कि अब तक संक्रमण जैसी कोई समस्या नहीं है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित सरकारी (डॉ. भीमराव आंबेडकर) अस्पताल के एडवांस कॉर्डियक इंस्टीट्यूट (एसीआइ) के डॉक्टरों ने सर्जरी के बाद कहा भी कि जब मरीज को अस्पताल लाया गया था, उसकी खुली छाती में मिट्टी और पानी भरा था। बहरहाल, अंततः सब ठीक हुआ और आज वह शानदार जीवन गुजार रहे हैं।

साथ बाइक से घर लौट रहा था। बादल पीछे बैठा था, बरसात हो रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक ब्रेक लगने से असंतुलित हुई और बादल सड़क किनारे लगे खंभे पर जा गिरा। खंभे के एक हिस्से ने उसकी छाती में गड्ढा कर दिया। वह बेहोश हो चुका था ...जब होश आया तब 48 घंटे बीत चुके थे, उसका ऑपरेशन हो चुका था, और मौत पर जिंदगी विजय पा चुकी थी।

SHIVALIK AGRO POLY PRODUCTS LTD.

Regd. Office: Plot No. 1, Sector 3, Industrial Area, Parwanoo (H.P.)
Phone Nos- 0172-2227087-88, Fax: 0172-2270349. Email:bljain@sappl.co.in
Website: www.shivalikagropoly.com CIN: U15131HP1976PLC003703

COMPANY NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and other applicable provisions that Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 20th September, 2018 to 25th September, 2018 (both days inclusive) for the purposes of Annual General Meeting to be held on Friday, 28th September, 2018 at 12.30 Noon at the Registered Office of the Company. Further, the record date has been fixed for 25th September, 2018 for the purposes of dividend @ 25% i.e. Rs. 2.50 per equity share to the members, as recommended by the board.

For SHIVALIK AGRO POLY PRODUCTS LTD.

Place: Mohali
Dated: 10th September, 2018

B.L. Jain
Company Secretary

भारत सरकार

लोक उद्यम चयन बोर्ड

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

में

निदेशक (तकनीकि/पी & पी)

पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं।

लोक उद्यम चयन बोर्ड में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि

29 अक्टूबर, 2018 (15.00 बजे तक) है।

जानकारी के लिए वेबसाइट

http://www.pesb.gov.in

में लॉग इन करे

...खिलाफ चौथी बार प्रदर्शन

...ठी आवाज

...भी आतंकवाद के खिलाफ मार्च निकाल चुका है।

इसमें भी आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ नारेबाजी हुई थी[illegible]डगाम के कई गांवों से होता हुआ यह मार्च चरार-ए-शरीफ में खत्म हुआ था। आतंकवाद के खिलाफ शुरू हुए इस तरह के मार्च को पैगाम-ए-मोहब्बत का नाम दिया है।

इसका आयोजन करने वाले जेकेएएफ के नेता फारुख अब्दुल गनी हैं, जो जम्मू-कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी (जेकेसीसी) का हिस्सा है। जेकेसीसी में कई स्थानीय एनजीओ और सामाजिक संगठन शामिल हैं जो घाटी में आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ हैं।

सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में वंजारा सहित छह पुलिसकर्मी बरी

राज्य ब्यूरो, मुंबई : गुजरात के गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी कौसर बी एवं सहायक तुलसीराम प्रजापति के एनकाउंटर मामले में बांबे हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने गुजरात एटीएस के पूर्व प्रमुख डीजी वंजारा एवं पांच अन्य पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया है। इस मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने गुजरात के आइपीएस अधिकारी राजकुमार पांडियन, गुजरात के एटीएस प्रमुख डीजी वंजारा, गुजरात पुलिस के अधिकारी एनके अमीन, राजस्थान काडर के आइपीएस अधिकारी दिनेश एमएन, गुजरात के आइपीएस अधिकारी विपुल अग्रवाल एवं राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल दलपत सिंह राठौड़ को आरोप मुक्त कर दिया था। लेकिन विशेष अदालत के फैसले को सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन और सीबीआइ ने पांच पुनरीक्षण याचिकाओं के जरिये बांबे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।